







# सम्पादकीय कोरोना के दौर में चुनाव

संक्रमण फैलने की गति इतनी तेज है कि निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी के बाद भी चुनाव प्रचार के परंपरागत तरीकों पर रोक लगानी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किए जाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। अखिरकार निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तिथियां घोषित कर दीं। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होंगे तो मणिपुर में दो चरणों में और पंजाब, उत्तराखण्ड और गोवा में एक चरण में ही। नीति जे के लिए 10 पार्च का इंतजार करना होगा। निर्वाचन आयोग ने नामांकन और मतदान तिथियों की घोषणा करते ही 15 जनवरी तक चुनावी रैलियाँ, नुकड़ सभाओं, रोड शो, पदयात्रा आदि पर भी रोक लगा दी है। ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। संक्रमण फैलने की गति इतनी तेज है कि निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी के बाद भी चुनाव प्रचार के परंपरागत तरीकों पर रोक लगानी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किए जाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इसके लिए तैयार रहें कि उन्हें 15 जनवरी के बाद भी डिजिटल चुनाव प्रचार पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसमें थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि डिजिटल चुनाव प्रचार की कुछ सीमाएं हैं। बावजूद इसके इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले भी बांगल, तमिलनाडु आदि में राजनीतिक दल डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार कर चुके हैं।

यह भी किसी से छिपा नहीं कि आज हर दल इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय है। मजबूरी में ही सही, यदि डिजिटल चुनाव प्रचार की संस्कृति विकसित होती है तो यह उचित ही होगा। इससे न केवल दलों और जनता के समय एवं संसाधन की बचत होगी, बल्कि प्रशासन को रैरेलियों, रोड शो आदि के लिए जो तमाम प्रबंध करने पड़ते हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। जब डिजिटल तकनीक जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है तो फिर चुनाव प्रचार की शैली भी बदलनी चाहिए। चूंकि चुनाव वाले पांच राज्यों में सबसे अधिक आवादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसलिए पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर के मुकाबले उस पर सबसे अधिक दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। इसलिए और भी, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव वाले पांच राज्यों में पंजाब को छोड़कर शेष चार में भाजपा सत्ता में है। कहां कितना कांटे का संघर्ष होता है, यह चुनाव नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तो ही है कि चुनाव प्रचार जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहे तो बेहतर। निर्वाचन आयोग को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि न तो आदर्श आचार सहिता का उल्लंघन होने पाए और न ही किसी तरह की धांधली। उसे दुष्प्रचार करने वाले तत्वों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि डिजिटल संसार में ऐसे तत्व भी खूब हैं।

## ખિસિયાઈ ભાજપા ખંભા નોચે

पंजाब चुनाव में भाजपा के लिए आसार पहले ही ठोक नहीं थे। कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक के बावजूद भाजपा को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिससे वह सुर्खियों में आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने नाम के साथ चलाए जाने वाले जुमले, मोदी है तो मुमकिन है, को सच साबित कर दिया। यानी जिस भाजपा को अब तक पंजाब में खास तवज्जो नहीं मिल रही थी, उसे मोदीजी की सुरक्षा व्यवस्था के बहाने चर्चा में आने का मौका मिल गया बुधवार 5 जनवरी को जिस तरह फिरोजपुर में उनकी रैली रद्द हुई, उसका ठीकरा अब कांग्रेस के सिर मढ़ते हुए भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लग गई है। इसका प्रमाण है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी, जिसमें वे कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे, जैसी बात कह रही हैं। पंजाब एक अरसे से संवेदनशील राज्य रहा है और बड़ी मुश्किल से यहां अमन बहाती हुई है। लेकिन मात्र चुनावों में जीत के लिए जिस तरह की सनसनी कायम करने की कोशिश भाजपा कर रही है, वह निर्दनीय है। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले के 15 मिनट तक रुकने का मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच ही चुका है, इस पर राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री ने मिलकर चर्चा कर ली है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से ट्रीट कर बताया गया है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की है। पंजाब सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके बाद कम से कम भाजपा को शांत रहकर रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन भाजपा के लिए यह छोंका फूटने के समान है, इसलिए वो इस मौके को पूरी तरह भुना रही है। प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में जाते हैं तो उनका मिनट दर मिनट का कार्यक्रम और आने-जाने की व्यवस्था, सब तय होते हैं। इस बारे में राज्य पुलिस सुरक्षा के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं होती, उसके साथ विशेष सुरक्षा दल यानी एसपीजी तालमेल बना कर चलती है। बुधवार को मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकाप्टर से दौरा रद्द हुआ और सड़क मार्ग से जाना तय हुआ। यह फैसला उच्च स्तर से हुआ होगा, इसलिए केवल कांग्रेस को इस तरह दोषी ठहरा कर संदेह का माहौल बनाना, एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना कठई सही नहीं है। वैसे भी प्रधानमंत्री का सुरक्षा चक्र काफी मजबूत होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे पहले पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई चलती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और फिर दो गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद दाईं और बाईं तरफ से दो गाड़ियां रहती हैं जो बीच में चलने वाली प्रधानमंत्री की गाड़ी

# फिरोजपुर की

## उपेन्द्र प्रसाद

को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के जवान तैनात रहते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के चारों तरफ रहते हैं और उनके साथ-साथ चलते हैं। निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे की दूसरी पंक्ति में तैनात रहते हैं। तीसरे सुरक्षा चक्र में नेशनल सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) होते हैं। चौथे चक्र में अर्ड्सुरक्षा बल के जवान और विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी होते हैं। और सुरक्षा के पांचवें चक्र में कमांडो और पुलिस कवर के साथ कुछ अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस वाहन और एयरक्राफ्ट रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अति सुरक्षा वाली बुलेटफ्लीटमडब्ल्यू 7 कार से सफर करते हैं। उनके कफिले में दो डमी कार के अलावा एक जैमर से लैस गाड़ी भी तैनात रहती है। सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था इसलिए है, क्योंकि देश ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के दुखदायी प्रकरण देखे हैं।

# आधार मतदान

## डॉ. अंजीत रानाडे

चाहे किसान हों या कांग्रेस, भाजपा से उनके राजनीतिक, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर इसके लिए हत्या की साजिश जैसे आरोप काफी गंभीर हैं। भाजपा को इस किस्म की राजनीति से बचना चाहिए। वैसे भी पंजाब में हाशिए पर जा चुकी भाजपा के लिए भविष्य में कोई बेहतर उम्मीद नहीं दिख रही। कल प्रधानमंत्री की जो रैली रह रुई, वो एक तरह से भाजपा के फयदे में ही रही। क्योंकि भाजपा का दावा था कि कम से कम 5 लाख लोग इस रैली में पहुंचेंगे, मगर सभास्थल पर खाली पड़ी कुर्सियां गवाह थीं कि लोगों ने पहले ही मोदीजी को न सुनने का मन बना लिया था। भाजपा ने शुरूआती तैयारियों में 32 सौ बसों की व्यवस्था की थी, ताकि लोगों का रैली में पहुंचाया जा सके। लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए जब यह अहसास भाजपा की राज्य इकाई को हुआ कि यह रैली फलौप शो साबित हो सकती है, तो बाद में बसों की संख्या घटाकर 5 सौ कर दी गई थी।

**धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, हिंदू धार्मिक परंपराओं के भी खिलाफ है हिंदुत्व**



ही नहीं रखते थे, साम्राज्यवादी शासन के संदर्भ में, अपने धर्मविलंबियों के लौकिक हितों के साथ अपनी आस्था को जोड़ते और वास्तव में उनके लौकिक हितों के तकाजों से अनुशासित भी करते थे। एक साम्राज्यवादविरोधी सर्वभारतीय एकता, इन लौकिक हितों की सबसे बुनियादी शर्त थी। इसीलिए, गांधी, आजाद और दूसरे अनेकानेक राष्ट्रवादी बौद्धिक-सांस्कृतिक-धार्मिक नेताओं ने, खुद धार्मिक परंपराओं, विश्वासों को इस प्रकार पुनर्पूरित व्याख्यायित और यहां तक कि पुनर्सूजित किया था, जो उन्हें इस सर्वभारतीय एकता के अनुरूप ढाले। यह उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में उठे सुधार आंदोलनों का अगला कदम था। अचरज नहीं कि गांधी ने जहां एक ओर, हिंदू धर्म की ऐसी कल्पना पर जोर दिया, जिसमें अन्य धर्मों का आदर एक प्रमुख मूल्य हो, तो दूसरी तिंहूं धर्म की ऐसी कल्पना का तकाजा किया, जिसमें छुआछूत पाप हो। कहने की जरूरत नहीं है कि सावरकर हों या जिना, धार्मिक पहचान के सिर्फ इस्तेमाल में दिलचस्पी रखने वालों की इस तरह के सुधारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी बल्कि वे तो इन्हें अपने धार्मिक समुदायों को बांटने वाला मानकर, दबाने की ही कोशिश

श्रेणियों में बांटा ही नहीं जा सकता था और अंगरेजों ने जब भारत में जनगणना की शुरूआत की थी, आबादी का अच्छा-खासा हिस्सा, हिंदू, मुसलमान या ईसाई जैसी प्रमुख धार्मिक पहचानों के दायरे से बाहर ही था। यह दूसरी बात है कि जनसंख्या की गिनती की इस प्रक्रिया से निकले, सांप्रदायिक होड़ के राजनीतिक तकाजों ने, कुछ ही समय में, इन समझौतों में से अधिकांश को, प्रमुख धर्मों में से किसी एक के खाने में धकेलने का ही काम किया। भारतीय उपमहाद्वीप के इस यथार्थ को देखते हुए, रसीभर अचरज की बात नहीं है कि यहाँ कभी भी और कोई भी उल्लेखनीय राज्य, धर्म-अधारित नहीं रहा। अशोक के प्रसिद्ध धर्मदिशों से लेकर, अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन-ए-इलाही तक, भारत में अपने ही तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्य की ही परंपरा रहने के साक्ष्य हैं। इस परंपरा में शासक, अपने धर्म से भिन्न प्रजा की धार्मिक परंपराओं के प्रति वैरभाव रखना तो दूर, आम तौर पर उनका आदर किया करता रहा है और वास्तव में प्रजा की धार्मिक परंपराओं को, जहां तक हो सके खुद भी अपनाया करता था। इसी वास्तविक भारतीय परंपरा को, ब्रिटिश राज के सदर्भ में विकसित हुई सुधार अंदोलनों तथा अंततः राष्ट्रीय अंदोलन की परंपरा ने आगे बढ़ाया और स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष संविधान के रूप में इसे मूर्त रूप दिया, जो न सिर्फ जटिल-धर्म-भाषा आदि के विभाजनों से ऊपर उठकर, सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी करता है बल्कि सभी कमज़ोर तबकों तथा तमाम अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान भी करता है, ताकि बराबरी को वास्तविक बनाया जा सके। इसी समूची विकासधारा के विरोधी स्वर के रूप में, ब्रिटिश सामराज्यी इतिहास दृष्टिष्ठाने, भारत में हिंदू और मुस्लिम, दो विरोधी राष्ट्रों की मौजूदगी के विचार के बीच बोए और सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने की दावेदार कांग्रेस के नेतृत्वाली राष्ट्रीय धारा के विपीरी, अकेले-अकेले मुस्लिम और हिंदू संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले संगठनों को बढ़ावा देने के जरिए, सामराजी हुकूमत ने संप्रदाय आधारित परवर्जी राष्ट्र की इन कल्पनाओं को पाला-पोसा। इसी क्रम में सावरकर ने हिंदुत्व के नाम से, हिंदू धार्मिक परंपराओं से नितांत भिन्न, एकांगी हिंदू पहचान पर आधारित, परवर्जी राष्ट्र की अपनी संकल्पना पेश की, जिसे गोलवलकर ने हिंटलर के नाजी मॉडल से जोड़कर और नरसंहारकारी रूप से सांप्रदायिक बना दिया। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान के रूप में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाई गई। ब्रिटिश हुकूमत की मदद से, मुस्लिम लीग तो अलग पाकिस्तान बनवाने में कामयाब हो गई, लेकिन उसके हिंदू समकक्ष, हिंदू महासभा और आरएसएस की, शेष भारत पर नाजी मॉडल का अपना हिंदू राष्ट्र उर्फ हिंदुत्व थोपने की कोशिश को, भारतीय जनता ने, हिंदुओं के प्रचंड बहुमत के बावजूद,

# फिरोजपुर की स्थगित रैली तिल का ताढ़ बनाया जा रहा है

उपन्द्र प्रसाद

प्रधानमंत्री को एक रैली फिरांजपुर में होना था। उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करना था। उसवें पहले उन्हें विकास की अनेक परियोजनाओं की घोषणा करनी थी, लेकिन उनकी सभा नहीं हो सकी, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। वे चाहते थे वहां पहुंच सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा और समय लगता। थोड़ा और समय लगाने से बेहतर उन्होंने रैली को स्थगित कर देना ही उचित समझा और वे बिना घोषण किए, दिल्ली वापस आ गए। उसके बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक हुंगामा कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में पंजाब सरकार विफल रही। इसके लिए भाजपा के नेता पंजाब की भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कुछ पंजाब की चत्ती सरकार को बर्खास्त कर देने की मांग तक कर रहे हैं। यह सच है कि रैली नहीं होना गलत है और यह भी सच है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित रास्ते उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन इस पर जो हांगामा हो रहा है, वह गलत है। इसके लिए पंजाब सरकार की जो भारी आलोचना की जा रही है, वह गलत है। जिस तरफ प्रधानमंत्री को विवश होकर वापस आना पड़ा, उसी तरफ की विवशता पंजाब की पुलिस की भी रही होगी। दरअसल पंजाब के किसान प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं और वह मांग कर रहे हैं कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान जिन पर मुकदमे किए गए, उन्हें वापस लिया जाय। पंजाब सरकार ने मुकदमे वापस लेने के बात मान भी ली है, लेकिन अन्य राज्यों में भी मुकदमे हुए हैं। वहां से भी सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। किसानों की दूसरी मांग है कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाय औं उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियां दी जाय न्यूनतम मूल्य समर्थन की उनकी मांग भी अपनी जगह प

# आधार मतदान

## डॉ. अंजीत रानाडे

भारत गणराज्य की घोषणा के एक दिन पहले यानी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट-आरपीए) में निहित कानूनी ढंगे के भीतर कार्य करने वेलिए बाध्य है। केवल संसद को ही आरपीए में संशोधन करने का अधिकार है जो समय-समय पर किया जाता रहा है। पिछले 70 वर्षों में इसमें कई बार संशोधन किया गया है। एक उद्घेखनीय संशोधन अधिकरणों से उच्च न्यायालयों में चुनाव याचिकाओं का हस्तांतरण था। यहाँ वजह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जहाँ 1975 में उनके चुनाव को शून्य और अवैध घोषित कर दिया गया था। पिर भी आरपीए में बड़े संशोधन बहुल लंबे समय से लंबित हैं। उदाहरण के लिए पिछले के वर्षों से विधि आयोगों की विभिन्न सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। खुद चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और भारत

कायम है। उनकी ये मार्गें केन्द्र सरकार से हैं। और वे आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश में अनेक स्थानों पर जब-तब सड़के जाम कर दी जाती हैं। रेल लाइन को भी आंदोलन से कभी-कभी प्रभावित होना पड़ता है। वैसे ही माहौल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में वह सभा होनी थी। आंदोलन पहले से ही चल रहा है। और आंदोलनकारियों के निशाने पर नरेन्द्र मोदी ही है। जाहिर है, जब उनका कार्यक्रम बना, तो किसानों की मुखरता और भी बढ़ गई। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत कमज़ोर है। वह गठबंधन करके ही चुनाव जीतती है। अकेले उसकी जीत का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। आम आदमी पार्टी के उदय ने उसके आधार को और भी कमज़ोर कर दिया है। एक तो आधार बहुत ही कम और दूसरी तरफ से बीजेपी का किसानों और उनके हमदर्दी द्वारा हो रहा भारी विरोध। इन दोनों के कारण वहां भाजपा की हालत बेहद पतली है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवगठित पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो रहा है, पर यह ही नहीं पता है कि अमरिंदर सिंह की खुद राजनैतिक ताकत पंजाब में कितनी है, तो भाजपा को उससे कितना लाभ होगा, यह किसी को नहीं पता। पंजाब विधानसभा में भाजपा अपना खाता भी खोल पाएगी, इसके बारे में भी कोई दावे से नहीं कह सकता।

A collage of Aadhar cards and a Aadhar card application form. The top half features a large, bold, black text "आधार कार्ड लिंकिंग". Below it, on the left, is a stack of Aadhar cards showing various demographic details like name, date of birth, gender, address, and photo. On the right, there is a white application form with the Indian tricolor at the top, followed by sections for "भारत सरकार" (Government of India) and "मुख्यमंत्री आवास" (Chief Minister's Office). The form contains fields for personal information and a QR code.

सरकार को पत्र लिखकर वह सुनिश्चित करने को कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चुनाव सुधार कानून संसद से पारित किए जाएँ लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आयोग के सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक आपराधिक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराना रहा है। अपराधी में अयोग्यता का मापदंड बहुत कमज़ोर है और वह गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले निर्वाचित सांसदों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने में विफल रहा है।

संसद द्वारा काइ कारवाइ न किए जान के कारण उच्चतम न्यायालय ने कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। उसके आदेश की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)ध् मतपत्र पर

सीटें जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई समर्थक आधार नहीं है और जो कुछ लोग उसके समर्थन में हैं भी, वे भाजपा विरोधी माहौल के कारण चुप ही रहते हैं, इसलिए मोदी की प्रस्तावित सभा में लोग पहुंचे ही बहुत कम थे। वहां 70 हजार कुर्सियां लगाई गई थीं, लेकिन खबरों के अनुसार मुश्किल से 700 लोग ही पहुंचे थे। लोगों की कम उपस्थिति का एक कारण यह भी था कि आंदोलनकारी किसान भाजपा समर्थकों को उस सभा में जाने से रोक भी रहे थे। जाहिर है, कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उसी तनावपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री ने बहुत ही आखिरी समय में अपना मार्ग बदलने का फैसला किया। वे थटिंडा में अपने हवाई जहाज से उतरे थे। वहां से वे हेलिकॉप्टर से सभा स्थल पर जाने वाले थे। प्रधानमंत्री की बात मानें, तो खराब मौसम के कारण उहोंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। सड़क मार्ग से जाने में ज्यादा समय लगता और उस बीच कुछ और लोग सभा स्थल पर आ जाते और खराब मौसम का खतरा भी नहीं रहता। इसलिए सड़क मार्ग से जाने का उनका निर्णय गलत नहीं था। लेकिन सड़क पर जहां तहां भाजपा का विरोध हो रहा था। भाजपा समर्थकों को भी सभा स्थल पर जाने से रोका जा रहा था और उसी बीच प्रधानमंत्री ने खुद सड़क से जाने का फैसला कर लिया और वही हुआ, जो होना निश्चित था। आंदोलनकारी किसानों ने उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि वे किसान कह रहे हैं कि वे वहां भाजपा समर्थकों को सभा स्थल पर जाने से रोकने के लिए एकत्र हुए थे और उन्हें पत नहीं था कि प्रधानमंत्री भी वहां से गुजरने वाले हैं। उहोंने हटाने के लिए जब पुलिस ने प्रधानमंत्री के आने की बात की, तो उहोंने विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि पुलिस झूठ बोलकर वहां से हटाना चाहती है, ताकि भाजपा समर्थकों का रास्ता साफ़ हो सके। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री की कार और किसानों के आंदोलन स्थल में दूक लगानीट का दूरा था, जाहिर ही किसानों को पता ही नहीं होगा कि उनके नाम के कारण प्रधानमंत्री पलाइओवर पर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग भी कर सकती थी, लेकिन उससे हिंसा फैलने की आशंका थी, इसलिए वैसा नहीं किया गया। शायद पुलिस को कुछ समय मिलता तो वे किसानों को समझा बुझा कर वहां से हटा देते, लेकिन प्रधानमंत्री ने पुलिस को और समय नहीं दिया और 15 से 20 मिनट का इंतजार कर वे वापस लौट आए। और उसके बाद हंगामा हो रहा है इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं। राजनेताओं के विरोध होते रहे हैं। इन्दिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आंदोलनकारी छात्रों ने प्रवेश तक नहीं करने दिया था। और अनेक ऐसे मामले अतीत में मिल जाएंगे, जिनमें प्रधानमंत्री का रास्ता बाधित किया गया है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। यह लोकतंत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार के पास पुलिस बल होता है। वह चाहे, तो इस तरह के प्रतिरोध को कुचल दे, लेकिन राजनैतिक प्रक्रिया को पुलिस बल से कुचलना कोई अच्छी बात नहीं है। जब आंदोलनकारी हिंसक हो जाएं, तब तो इसे सही माना जा सकता है, लेकिन पंजाब के किसान अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं और उनके खिलाफ गोली चलाना पहला क्या, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प भी नहीं हो सकता। इसलिए किसी पर दोष लगाने से बेहतर है कि इस मामले को भुला दिया जाय। इसे यह सामान्य राजनैतिक प्रक्रिया का हिस्सा मान लिया जाय। पंजाब के कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है। उसे भी बोट चाहिए। पिर कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री के लिए रास्ता साफ़ करने के लिए किसानों पर बल का प्रयोग करती। सुरक्षा देना पुलिस का काम है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा बाधित हुई हो, वैसा कुछ दिख नहीं रहा।

# आधार मतदाता कार्ड लिंकिंग से होंगी नई मुश्किलें

डा. अजात रानाड

संसद आर रंज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र आर निष्पक्ष चुनाव कराने को जिम्मेदारी संभालने वाले निर्वाचन आयोग पर भारत को गवर्न है। चुनाव आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के लिए प्रतिष्ठित है जो सुनिश्चित करता है कि चुनाव में भाग लेने प्रत्याशियों को समान अवसर मिलें तथा लोबिनियां किसी डर के मतदान करें। चुनाव आयोग की स्थापना भारत गणराज्य की घोषणा के एक दिन पहले यानी 2 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (रिप्रेजेन्टेशन ऑफ़ पीपुल्स एक्ट आरपीए) में निहित कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करने वे लिए बाध्य हैं। केवल संसद को ही आरपीए में संशोधन करने का अधिकार है जो समय-समय पर किया जाता रहा है। पिछले 70 वर्षों में इसमें कई बार संशोधन किया गया है। एक उल्लेखनीय संशोधन अधिकरणों से उच्च न्यायालयों में चुनाव याचिकाओं का हस्तांतरण था। यह वजह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जहां 1975 में उनके चुनाव को शून्य और अवैध घोषित कर दिया गया था। पिर भी आरपीए में बड़े संशोधन बहुल लिए समय से लंबित हैं। उदाहरण के लिए पिछले कवर्षों से विधि आयोगों की विभिन्न सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। खुद चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री और भारत

सरकार को पत्र लिखकर वह सुनिश्चित करने को कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चुनाव सुधार कानून संसद से पारित किए जाएँ लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आयोग के सबसे महत्वपूर्ण सुझावों में से एक आपराधिक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराना रहा है। अपराधी में अयोग्यता का मापदंड बहुत कमज़ोर है और वह गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले निर्वाचित सांसदों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने में विफल रहा है।

संसद द्वारा काइ कारवाइ न किए जान के कारण उच्चतम न्यायालय ने कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। उसके आदेश की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)धूम पत्र पर

नोटा (नन ऑफदी एबोव- उपरोक्त में से कोई भी नहीं) बटन आया। इस तरह हम सजायापता सांसदों को संसद में बैठने से तत्काल रोक सकते हैं भले ही उन पर चल रहा आपराधिक मामला अपील के लिए उच्च न्यायालय में गया हो। इसी तरह 2003 के निर्णय की बदौलत मतदाताओं को उम्मीदवारों के शपथ पत्र के कारण उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चल जाता है। इनमें से कोई भी सुधार संसद द्वारा नहीं लाया गया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से ये सुधार किए हैं। राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की जनता की इच्छा आज भी अदालतों में लंबित है। यह भी एक महत्वपूर्ण सुधार है। जब संसद ने खुद चुनाव सुधार करने का काम किया है तो उसने अक्सर संदिग्ध इशारे से ऐसा किया है। इसका उदाहरण राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनावी बांड शुरू करने का है। यह कानून दानदाता या प्रासकर्ता की पहचान बताने को पूरी तरह से नकारता है। शब्द श्पारदर्शिता का प्रयोग सरकार द्वारा जनता की सार्वजनिक व निजी गतिविधियों पर लगभग रोक लगाने के अर्थों में किया गया है। आरपीए पर संसद की कार्रवाई का एक और ताजा उदाहरण पिछले महीने पारित संशोधन है। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार का लिंकेज है। इसे 20 दिसंबर को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। अगले दिन राज्यसभा में इस पर मतदान की जोरदार मांग के बावजूद





**ईशा गुप्ता (Esha Gupta)** ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। उन्होंने अपनी इंस्टास्टोरी के जरिए फैंस को ये खबर दी है और साथ ही इस बात की भी उम्मीद जताई है कि वह जल्दी ही ठीक भी जाएंगीं। एकट्रेस के इस जानकारी को साझा करते ही उनके फैंस लिए दुआएं कर रहे हैं।

# ईशा गुप्ता

## की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, पोस्ट शेयर कर दी सेहत की जानकारी

मनोरंजन जगत से हर रोज सितारों के कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने की खबर आ रही है। रविवार को ही काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi), नफीसा अली, अरिजीत सिंह (Arijit Singh) और बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज (Satyraj) के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सापेन आई थी। अब कोरोना संक्रमित सितारों की लिस्ट में नया नाम ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का है। जी हां, बॉलीवुड एकट्रेस ईशा गुप्ता भी कोरोना वायरस (Esha Gupta Covid Positive) की चपेट में आ गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है।

ईशा गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। उन्होंने अपनी इंस्टास्टोरी के जरिए फैंस को ये खबर दी है और साथ ही इस बात की भी उम्मीद जताई है कि वह जल्दी ही ठीक भी जाएंगीं। एकट्रेस के इस जानकारी को साझा करते ही उनके फैंस लिए दुआएं कर रहे हैं।

ईशा ने अपने पोस्ट में लिखा है— ‘पूरी सावधानी बरतने के बाद भी मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हूं, मैं सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हूं और मैंने खुद को अपने घर में क्लारंसी कर लिया हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं वहां से भी ज्यादा मज़बूत बनकर वापस आऊंगीं। आप सभी से निवेदन है कि सुरक्षित रहें और मास्क जरूर पहनें। अपना पूरा ध्यान रखें और मास्क को ऊपर करना ना भूलें।’

इससे पहले भी कई सितारे कोरोना की तीसरी लहर में महामारी की चपेट

में आ चुके हैं, जिनमें से कुछ ठीक हो चुके हैं तो कुछ की जंग अभी भी जारी है। इनमें करीना कपूर, महीप कपूर, शनाया कपूर, अर्जुन बिजलानी, नकुल मेहता, जानकी पारेख, अर्जुन कपूर, सीमा खान, अमृता अरोड़ा, स्वरा भास्कर, प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा जैसे कई सितारे शामिल हैं। महामारी के चलते फिल्मों की शूटिंग और रिलीज डेट भी एक बार फिर प्रभावित होने लगी हैं।

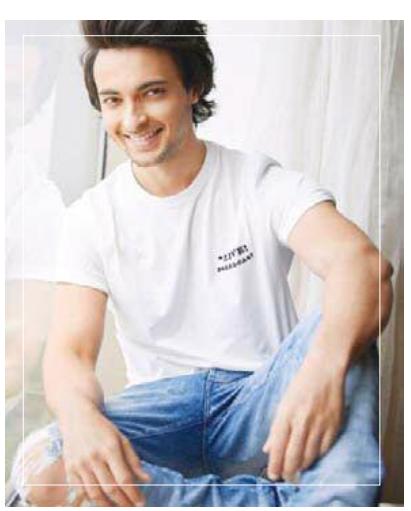


## आयुष शर्मा ने बताया करियर प्लान, मरती भरी लव स्टोरी में करना चाहते हैं काम

भाईजान (Salman Khan) के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा (Aayush Sharma) बीते दिनों अपनी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ' (Antim: The Final Truth) को लेकर काफी चर्चा में रहे। दर्शकों को उनकी ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। आयुष ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में पहचान बना ली है। इस बीच हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो अपनी हालिया रिलीज फिल्म पर बात करते नज़र आ रहे हैं। साथ ही उनके करियर प्लान के बारे में भी उन्होंने बताया।

आयुष (Aayush Sharma) ने कहा, मुझे बॉलीवुड से प्यार है और मैं किसी भी एक कैटिग्री या जॉनर में नहीं रहना चाहता और न ही मैं एक बॉक्स में बंद रहना चाहता हूं, मैं कॉमेडी, रोमांस, इंटेंस लव स्टोरी और एक्शन सहित हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि वो लवयात्री जैसी मजेदार लव स्टोरी करना पसंद करेंगे, जो लोगों को हँसाए। यह एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर जैसा है, जिसे लोग बिना किसी तनाव के देख सकते हैं।

एक्टर आयुष शर्मा (Aayush Sharma) ने कहा, मैं एक पौरियड



फिल्म भी करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि इतिहास में वायरल जाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। मैंने अपना हॉरीजन हर चीज के लिए खोल दिया है। मेरे लिए यह तय करना जल्दबाजी होगी कि मैं किसमें अच्छा हूं और उस पर कायम रहूंगा। अंतिम में राहुलिया जैसे किरदार को निभाने का मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। यह किरदार इतना दमदार था, जो बहुत कम फिल्मों में ऑफर होता है। आयुष (Aayush Sharma) का कहना है कि वो खुद के किरदार को बार-बार नहीं दोहराएंगे। एक कलाकार के नाते रास्ते में कुछ गलतियां जरूर करूंगा, लेकिन उनका लक्ष्य होगा कुछ सीखने के और आगे बढ़ने का।

बता दें कि आयुष ने साल 2018 में आई फिल्म लवयात्री (Loveyatri) से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसे अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है। जबकि इसका प्रोडक्शन सलमान खान ने ही किया है। हालांकि, ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। ऐसे में इसका जादू पर्दे पर नहीं चला।

**Bhool Bhulaiyaa 2: विद्या बालन फिर बनेंगी मंजुलिका, निर्देशक अनीस बज्मी ने किया कंफर्म**



बॉलीवुड की 'शेरनी' यानी विद्या बालन (Vidya Balan) ने अपने करियर में कई बार ऐसे किरदार निभाए हैं, जिसके कारण लोग उनकी अदाकारी के दीवाने हैं। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया' याद है। आपको, जिसमें विद्या ने 'मंजुलिका' बन लोगों के होश उड़ा दिए थे। एक बार फिर लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए विद्या बेयार हैं। विद्या, कार्तिक आर्यन, कियरा आडवाणी और तब्बू की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) में नज़र आएंगी। हार्दर-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 2' का दर्शक बेसब्री से इतजार कर रहे हैं।

नवंबर में रिलीज होगा 'भूल भुलैया 2'

'भूल भुलैया (Bhool Bhulaiyaa)' 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में थे। शाइनी आहूजा, अमिता पटेल, परेश रावल और राजपाल यादव भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) मिथ्ये साल जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चक्र में फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकी और फिल्म की रिलीज पर ब्रेक लग गया। अब इस मेंकर्स इस साल नवंबर में फिल्म को रिलीज करने का प्लान रख रहे हैं।

**Bhool Bhulaiyaa 2 में 'मंजुलिका'**

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी ने कंफर्म किया है कि 'मंजुलिका' उनका सबसे पसंदीदा किरदार है और अगर फिल्म भूल भुलैया है तो निश्चित ही वो भूल भुलैया 2 में दिखाई देंगी। इस बार कहानी भूतों पर रह है। मेकर्स फैंचाइटी को रिवेट करना चाहते थे इतनालिए उन्होंने वहां नाम चुना है।

Parineeta से किया बॉलीवुड करियर का शुरूआत टीवी के हिट शो 'हम पांच' से घर घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली विद्या ने एक कल्ट रोमांटिक फिल्म 'परिनीता (Parineeta)' से अपने बॉलीवुड करियर का शुरूआत की। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त और सैफ अली खान नज़र आए थे।

'शेरनी' से सुर्खियों में रही विद्या

आपको बता दें कि विद्या हाल ही में फिल्म 'शेरनी' को लेकर सुर्खियों में रहीं। मनुष्य और पशुओं के बीच टकराव और समाज में राजनीतिक दबाव अरोड़ा वाली फिल्म 'शेरनी' में विद्या बालन ने वह अधिकारी विद्या विस्टेंस का रोल प्ले कर एक बार पिर अपनी दमदार अवधागी दिखाई।

**कपिल शर्मा को गिरी से शादी लगती थी नामुमकिन, बोले—मेरी कमाई से ज्यादा थी उसकी कार की कीमत**



पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) जल्द ही नेटफिल्म्स पर डेब्यू करने वाले हैं। इस शो में भी कपिल लोगों जमकर हंसाने वाले हैं। कपिल का यह स्टैंड अप कॉमेडी शो (Kapil Sharma Stand up Comedy) 28 जनवरी से स्ट्रीम होने वाला है। इस शो के कुछ प्रोमो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कपिल ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत से पाया है। अपने करियर के दौरान कपिल कई बार कंट्रोवर्सी के भी शिकार हुए। यहां तक कि ऐसी भी खबरें सामने आईं कि वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन के भी चले गए थे, मगर फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हाल में, दिए गए एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा (Kapil Sharma Latest Interview) ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया।

**कपिल ने सुनाई अपनी लव स्टोरी**

कपिल शर्मा ने इस इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाए। उन्होंने पती गिरी चत्रथ (Kapil Sharma Wife Ginni Chatrath) के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा, 'गिरी मुझसे 3-4 साल जूनियर थी। वह जालंधर में गर्ट्स कॉर्नर से ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं कमर्शियल आर्ट्स में पीजी डिप्लोमा। उस वक्त पैसों की भारी किट्स थी, लिहाजा, मैं पॉकेट मनी के लिए थिएटर करता था, जिसकी वजह से मैं दूसरे कॉर्नर के चक्र लगाता रहता था।' कपिल आगे कहते हैं, 'गिरी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी।'

# सेहत और खूबसूरती के रसीले इलाज



फलों व सब्जियों का रस निकालने का सही तरीका यह है कि इनके छिलके व बीजों को निकाल लें। इनके छिलकों में कई टाइपिस्क तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सेब के छिलके में एक तत्व होता है जो हानिप्रद हो सकता है। साथ ही आजकल फलों को पकाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन भी छिलकों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। छिलकों में कड़वापन भी होता है जो जूस के खारब व कड़वा कर देता है इसलिए छिलकों के साथ हमारे शरीर के लिए अच्छा है।

ताजे फलों व सब्जियों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये विटामिन, एन्जाइम व मिनरल के अच्छे स्रोत हैं परन्तु हम इनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाते, इसलिए अधिक से अधिक विटामिन व मिनरल पाने का सबसे उत्तम तरीका है फलों व सब्जियों के रस का सेवन। जूस कोकी तरल होता है इसलिए शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है। अब सबसे फला प्रसन आता है कि जूस कितना पिया जाए। इसका निर्धारण करना तो कठिन है परन्तु प्रतिदिन दो से चार गिलास रस हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बैसे तो हम हर रोज सब्जियां खाते हैं परन्तु इनको पकाने समय हम इनके सभी पौष्टिक तत्व नष्ट कर देते हैं।

इस प्रकार जो सब्जियां हम प्रयोग में लाते हैं, वे पौष्टिक रहते हैं इसलिए सब्जियों व फलों का रस ही उपयुक्त है जो हमें सभी पौष्टिक तत्व व तुरन्त शक्ति प्रदान करता है। आजकल बाजार में बहुत-सी कम्पनियों के जूस कैन उपलब्ध है परन्तु ये भी

पौष्टिकता रहते हैं। इन कैन जूसों को बनाने, पौष्टिक व बाजार में उपलब्ध होने तक कई हफ्ते लग जाते हैं और इन्हें समय में सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इनको सुरक्षित रखने के लिए इनमें कई तरह के रसायन मिलाएं जाते हैं जैसे सोडियम बेनजोएट, बेनजोइक एसिड आदि जो पौष्टिक तत्वों को नष्ट करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। इसलिए फलों व सब्जियों का रस जाता है निकालें। अगर आप पौष्टिकता चारते हैं तो रस निकालने के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। बाजार में भी आगे फलों का रस पिए तो अपने सामने ही निकलवाएं व पहले के कटे हुए फलों व सब्जियों का रस बिन्कलन न पिएं, बर्तोंक खुले पढ़े रहने के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। फलों व सब्जियों का रस अलग-अलग निकालें व इनका सेवन भी एक साथ न करें। यह उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी सब्जी या फल से एलर्जी है।

फलों व सब्जियों का रस निकालने का सही तरीका यह है कि इनके छिलके व बीजों को निकाल ले। इनके छिलकों में कई टाइपिस्क तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सेब के छिलके में एक तत्व होता है जो हानिप्रद हो सकता है। साथ ही आजकल फलों को पकाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन भी छिलकों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। छिलकों में कड़वापन भी होता है जो जूस के स्वाद को खारब व कड़वा कर देता है इसलिए छिलके ज्ञानकरक ही रस निकालें। फलों का रस कई रोगों को दूर करता है। यह पाचनतंत्र के लिए लाभप्रद है। इससे हमारा रक्त शद्द होता है व फलों के रस का सेवन शरीर से हानिकारक विषों को बाहर निकालता है। सब्जियों व फलों का रस शरीर में नये सेवनों के निर्माण में भी सहायक होता है। फलों के रस को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को कठिन त्रम नहीं करना पड़ता।

इसके अतिरिक्त रोगों के इलाज में फलों व सब्जियों के रस का प्रयोग किया जाता है। कब्ज में पालक, गाजर, बंदगोभी व सेब का रस लाभप्रद होता है। अस्थमा में सेब, खीरा, अदरक का रस लाभप्रद होता है। डायरिया जौ गर्मियों की एक आम बीमारी है व जिसे सोडियम बेनजोएट, बेनजोइक एसिड आदि जो पौष्टिक तत्वों को नष्ट करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। इसलिए फलों व सब्जियों का रस जाता ही निकालें। अगर आप पौष्टिकता चारते हैं तो रस निकालने के लिए थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। बाजार में भी आगे फलों का रस पिए तो अपने सामने ही निकलवाएं व पहले के कटे हुए फलों व सब्जियों का रस बिन्कलन न पिएं, बर्तोंक खुले पढ़े रहने के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। फलों व सब्जियों का रस अलग-अलग निकालें व इनका सेवन भी एक साथ न करें। यह उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी सब्जी या फल से एलर्जी है।

खीरा का रस, तरबूज का रस, टमाटर का स्वाद, सर्दे-



का रस, नींबू आदि त्वचा को आभा प्रदान करते हैं। फेस फैक के रूप में इनका प्रयोग तो युगने समय से होता आया है। अलू व खीरे के गोल टुकड़े कर 10-15 मिनट अंगों पर रखने से अंगों को ठंडक पहुंचती है व अंगों के ईर्झ-गिर्द पद्धि जाइया व काले घब्बे खाने हो जाते हैं। सेब के गूदे का फेस मास्क एक अच्छा कर्मजार है व तैलीय त्वचा के लिए अच्छा है।

## स्वाद भी बढ़ाता है पुदीना व सेहत का भी ख्याल रखता है

पुदीने का प्रयोग अक्सर चटनी बनाने में किया जाता है, तो कभी इसे गन्ने का रस निकालते समय प्रयोग किया जाता है। जिस भी व्यंजन में पुदीने का प्रयोग किया जाता है, उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन पुदीने सिर्फ़ आपके भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके कारण आपको कई तरह से वाले स्वास्थ्य समस्याओं में तो आप इसे बीतार और अधिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पुदीने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में-

पेट दर्द करे छमंतर

अगर आपका पाचन तंत्र सही तरह से काम नहीं कर रहा और पेट अच्छी तरह साफ़ न होने के कारण आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप पुदीने का प्रयोग करें। पेट दर्द को छमंतर करने के लिए आप पुदीने को पीस कर पानी में मिला लें और फिर उस पानी को छान कर पीएं। यह आपको पेट दर्द से तो राहत दिलाएगा ही, साथ ही इससे आपकी पाचन शक्ति भी बेहतर होगी।

वहाँ अपनके होने की स्थिति में आप पुदीने की पत्तियों का रस निकालकर उसमें नींबू का रस व शहद मिलाकर दिन में कम से कम तीन बार ले। आपको काफ़ी राहत महसूस होगी।

सांसों की बढ़वा से छुटकारा

कछुलोंगों को अक्सर सांसों से आने वाली दुर्घट की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे किसी के भी सामने बात करने से हिचकते हैं। अगर आपको भी इस समस्या से दो-चार होना पड़ता है तो आप पुदीने की पत्तियों की मदद लें। इसके इस्तेमाल के लिए आप भोजन करने के बाद पुदीने की कुछ पत्तियों को चबाएं। इससे आपकी सांसों से बढ़वा नहीं आएगा।

गले के लिए बरदान

अगर आपको गले में किसी तरह की समस्या है तो आप पानी में पुदीने की पत्तियां उबलाकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। इस पानी से गर्मिल करने पर आपको गले की हर समस्या से राहत मिलती है। यह नुस्खा गायकों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है।

ठीक करे चोट

अगर आपको चोट लग गई है तो आप पुदीने की मदद से अपने घाव को ठीक कर सकते हैं। दरअसल, पुदीने में एंटी-बैक्टीरियल पाया जाता है जो घाव को ठीक करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आप पुदीने की पत्तियां मसल कर इसका पेस्ट बना कर घाव वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा।

## चावल के पानी से बनाए बालों को मजबूत

अगर हम किचेन के एक ऐसे इंग्रीडिएंट्स की बात करें जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है और जो हर घर के किचेन में मिल जाएगा तो आपके दिमाग एक नाम ज़रूर आएगा और वो ही चावल। अगर आप अकेले रहती हैं शायद चावल वो इंग्रीडिएंट है जिसे बनाना बेहद आसान है। बस इसे पानी में डालें, उबालें और हो गया आपका खाना तैयार। आपने हेत्थ से जुड़े चावल के कई फायदों के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको इसके ब्यूटी फायदों के बारे में मालूम है? चौंकिए मत, ये सच है। जितना आसान चावल को बनाना है उतना ही आसान इसकी मदद से गलोइंग स्किन पाना भी है। इतना ही नहीं, ये आपके बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है।

डुमेंड बालों को करता है ठीक

आप अब एसर-स्टेनर और केमिकल्स के ज्यादा इस्तेमाल की बजाए से आपके बाल खारब हो जुके हैं, तो इस मालाले में चावल आपके लिए किसी मसीहे से कम नहीं है। शैम्पू करने के बाद चावल के पानी से हाफ़े हाथों से स्कैप्ट का मासाज करें। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर नॉर्मल पानी से बालों को धो।

कई बार हमारे बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा अमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स की कमी की बजाए ही वे जाती हैं। इसलिए अपने बालों को चावल के पानी से मासाज करें ताकि आपके बालों की मजबूती बने रहे और आपके घाव बाल के लिए अच्छा हो।

टूट कर आपके बालों को धो।



बालों में लाए चम्पक

